इस प्रकार कुछ मामलों में उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा लिए गए मूल्य राष्ट्रीय बीज निगम के मूल्यों की तुलना में कम हो सकते हैं ।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम समूचे देश में किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध कराने के लिये भरसक प्रयास कर रहा है । निगम राज्य कृषि विभागों और अन्य राज्य एजेंसियों के माध्यम से, अपने बिक्री काउंटरों के जरिए और अपने बीज विक्रेताओं के तंत्र के जरिए बीज का वितरण कर रहा है । राष्ट्रीय बीज निगम ने समूचे देश में 16 क्षेत्रीय कार्यालयों और 84 उप-एककों की स्थापना की है और इस समय निगम के पास 2,944 विक्रेताओं का तंत्र है, जो समूचे देश में फैला हुआ है । निगम द्वारा समय पर प्राप्त किए गए सभी मांग पत्रों पर निगम के उत्पादन कार्यक्रमों में विधिवत ध्यान दिया जाता है ।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अपने बीज की खरीद करता है, जबकि राष्ट्रीय बीज निगम समूचे देश में विभिन्न स्थानों पर अपने उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करता है । अतः बीजों के अन्तः राज्य वितरण के लिये परिवहन की लागत, उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम की लागत की तुलना में राष्ट्रीय बीज निगम के लिए अधिक है । इन दो निगमों की उत्पादन लागत के बीच इस अन्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा वसूल किये गये मूल्यों के बीच समानता का होना प्रायः संभव नहीं हो सकता है ।

तथापि, विशेष फसलों के लिये इन दो निगमों के मूल्यों के बीच अन्तर के अलग-अलग मामलों की आवश्यकतानुसार जांच की जाती है और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बिक्री मूल्यों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाता है, ताकि वे मूल्य उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम द्वारा लिए जाने वाले मूल्यों के समान हो ।

Construction of flats in pocket B-E, Janakpuri

2862. SHRIMATI USHA MALHOTRA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 387 given in the Rajya Sabha on the 3rd May, 1985 and State:

(a) whether the flats in Pocket B-E, Janakpuri have been completed and rleased for allotment in June, 1985; and

(b) if not, what are the reasons therefor and by when these are likely to be completed?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) No, Sir.

(b) The flats could not be released by the traget date primarily due to labour shortage with contractor on account of poor organisation of work by him. All efforts are being made to release the flats for allotment as soon as possible.

श्रमिकों के कल्याण के लिये स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

2863. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ स्वयंसेवी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है; यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक संगठन को कितना कितना अनुदान दिया गया और इन संस्थाओं के नाम क्या है ; और

(ख) इस संबंध में कितने संगठनों की जांच पड़ताल की गई है और ऐसे संगठनों की संख्या कितनी है जिन्हें इस बात का दोषी पाया गया है कि जिस प्रयोजन के लिए उन्हें अनुदान मंजूर किये गये थे उनका इस्तेमाल उन्होंने उन कामों के लिए नहीं किया और फिर भी, उन्हें अनुदान दिये गये है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां । स्वैच्छिक संगठनों को श्रमिकों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान दिए गए है । जहां तक श्रम मंत्रालय का संबंध है, गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदानों की राशि और ऐसे संगठनों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) अनुदानों की दूसरी और बाद की किश्तें 6 संगठनों को दी गई है और इन मामलों में संबंधित संगठनों से इस आशय के प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके है कि पहली वाली किश्तों का उसी प्रयोजनार्थ किया गया जिसके लिए वे दी गई थी । ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिनमें उक्त प्रमाण-पत्रों के प्राप्त हुए बिना और अनुदान दिया गया हो ।

विवरण

(रुपयों में)

क्रमांक	एजेंसी/संगठन का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान दिया गया अनुदान
1.	भारतीय बाल कल्याण परिषद्	1,00,000
2.	भारतीय ग्रामीण श्रमिक संस्थान, औरंगाबाद	90,935
3.	स्व-नियोजित महिला एसोसिएशन, अहमदाबाद	1,03,000
4.	मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	4,35,846
5.	कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद्	74,407
6.	भारतीय ग्रामीण श्रमिक संस्थान, औरंगाबाद (दूसरी योजना)	50,445
7.	स्व-नियोजित महिला एसोसिएशन, दिल्ली	12,500
8.	अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद्, बम्बई	40,000
9.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, हैदराबाद	75,000
10.	महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	56,525
11.	निर्मल सेवा समिति	78,580
12.	स्व-नियोजित महिला एसोसिएशन, अहमदाबाद	40,000

Transmission of photos electronically by PIB

2864. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the PIB propose to transmit photos electronically; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) Yes, Sir.

(b) Press Information Bureau is equipped to take up this service for three selected PIB offices, namely Lucknow, Hyderabad and Jalandhar. The equipment has so far been used only on a trial basis. It will be used to transmit photographs on a regular basis after technical arrangements with the Telecommunication Department are finalised.

2865. [*Transferred to the 22nd August, 1985*].